[2017] 2 एस. सी. आर. 62

गांधी डोड्डाबासप्पा उर्फ गांधी बासवराज

बनाम

कर्नाटक राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 631/2012)

28 फरवरी, 2017

[कुरियन जोसेफ और ए.एम. खानविलकर, जेजे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 302 - हत्या-अपीलार्थी द्वारा-अभियुक्त-उसकी बेटी की - हत्या करने का कारण यह बताया गया कि आरोपी हताश क्योंकि उसकी बेटी ने निचली जाति के एक लड़के से शादी की थी-पीडब्लू 18 (मृतक की सास) चश्मदीद गवाह थी-ट्रायल कोर्ट पीडब्लू-18 के साक्ष्य को खारिज करते हुए और यह मानते हुए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं था, उसे बरी कर दिया। उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया और आरोपी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया, लेकिन उसे अपराध के लिए दोषी ठहराया। धारा 304 (भाग I) आईपीसी और उसे 10 साल के कारावास की सजा-अपील अभियुक्त द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय को-न्यायालय ने अभियुक्त को सजा बढ़ाने के लिए कारणदर्शक नोटिस जारी किया-आयोजितः पीडब्लू-18 के पूरे संस्करण को असत्य नहीं माना जा सकता है-पीडब्लू-18 का संस्करण कि उसने सार्वजनिक शौचालय से मृतक के रोने की आवाज सुनी; आरोपी को खून से सना दरांती के साथ शौचालय से बाहर निकलते हुए और उस दरांती को पास के गोबर के गड्ढे में फेंकते हुए देखा-यह

संस्करण विश्वसनीय और सच्चा है-इस संस्करण को मजबूत उद्देश्य से मजबूत किया जाता है और आगे रक्त-सना हुआ दरांती की जब्ती और दरांती पर और मृतक के कपड़ों पर रक्त समूह के मिलान से पुष्टि की जाती है-हालांकि, इसमें से कोई भी अपवाद नहीं है। धारा 300 आईपीसी वर्तमान मामले में आकर्षित है, इसलिए मामले को पहले भाग के तहत नहीं लाया जा सकता है। धारा 304 आईपीसी-अभियुक्त धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है।

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 142 - उच्चतम न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील-द्वारा दायर की गई अभियुक्त-अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए-सजा बढ़ाने के लिए अदालत द्वारा जारी स्वतः संज्ञान नोटिस-मांगी गई अपील को वापस लेने की अनुमति-अभिनिर्धारितः अपीलार्थी को अपील वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है-कारण दर्शाएँ नोटिस को उसके स्थान पर ले जाना होगा। तार्किक अंत मूल कार्यवाहियों के लिए उत्तरदायी है अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता। अर्न्तगत 386 आर/डब्ल्यू 397 और 401 का सीआर.पी.सी और वर्तमान मामले में सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण अधिकार क्षेत्र अदालत-यह अदालत का कर्तव्य है कि वह मामले का फैसला करे, भले ही आरोपी अपनी अपील पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता हो। दोषसिद्धि के विरुद्ध-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस. एस. 386 आर/डब्ल्यू 397 और 401।

अपील को खारिज करना और कारण दस्सो नोटिस देना सजा को बढ़ाने के लिए, न्यायालय अभिनिर्धारित किया

1. इस न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद और प्रथम दृष्टया आश्वस्त होने के बाद, पक्षकारों को कारण बताए जाने का नोटिस जारी किया। अपीलार्थी-सजा बढ़ाने के

लिए अभियुक्त। इस पृष्ठभूमि में, अपीलार्थी को अपील वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कारण दर्शाओ नोटिस को उसके तार्किक अंत तक ले जाना होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 386 या धारा 397 और 401 के साथ पठित अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता के लिए विहित मूल कार्यवाहियां और इस मामले में, उच्चतम न्यायालय की पूर्ण अधिकारिता। यह इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मामले का फैसला करे, भले ही आरोपी दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी अपील पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता हो। [पैरा 20] [74-सी-ई, जी-एच]

विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 9 एससीसी 541; खेडू मोहटन और अन्य बनाम बिहार राज्य 1970 (2) एससीसी 450: [1971] 1 एससीआर 839; देव नारायण मंडल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2004 (7) एससीसी 257; पायलट यू.जे.एस चोपड़ा बनाम बॉम्बे राज्य [1955] 2 एससीआर 94-पर निर्भर था।

2.1 पी. डब्ल्यू. 18 को देखने के बाद पास के गोबर के गड्ढे में दरांती जब उसने उसे रुकने के लिए कहा और फिर मौके से भागने के लिए कहा, तो यह विश्वसनीय और सच्चा है। के इस संस्करण पर संदेह करने का कोई ठोस कारण नहीं है। पीडब्लू 18 उसी को स्वीकार करने पर, यह अनिवार्य रूप से होगा कि मृतक की हत्या के लिए अकेले आरोपी जिम्मेदार था, जो तथ्य उसके ऐसा करने के मजबूत उद्देश्य से पुष्ट होता है। इसके अलावा, पीडब्लू18 का यह संस्करण अन्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों से पुष्टि करता है। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में घटनास्थल से खून से सना दरांती की जब्ती और दरांती और मृतक के कपड़ों पर रक्त समूह "बी" का मिलान शामिल है। उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष और विशेष रूप से इसके विरुद्ध अपराध का निष्कर्ष अपीलार्थी (अभियुक्त) का दृष्टिकोण सही है। उच्च न्यायालय का यह

मानना सही था कि निचली अदालत ने पी. डब्ल्यू. 18 के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए तुच्छ कारण दिए। [पैरा 24] [77-ई-एच]

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास ए.आई.आर 1957 एससी 614: [1957] एससीआर 981--पर निर्भर था।

2.2 सन्देह का तरीका कि अभियुक्त का न केवल अपनी बेटी को मारने का मजबूत उद्देश्य था, बल्कि ऐसा करने के लिए जिम्मेदार था और मृतक की मृत्यु के लिए किसी और के जिम्मेदार होने की संभावना को बाहर करता है। अन्य सिद्ध परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पीडब्लू 18 के साक्ष्य की प्रभावकारिता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, यह एकमात्र संभावित दृष्टिकोण प्रतीत होता है और इस मामले में सही दृष्टिकोण है। जब्ती पंचनामा और वस्तुओं की बरामदगी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि निचली अदालत ने भी राय दी है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी यही साबित किया है। [पैरा 24] [80-बी-डी]

2.3 निचली अदालत ने राय दी कि यह हत्या का मामला था, लेकिन अपीलार्थी को इस निष्कर्ष पर संदेह का लाभ दिया कि अपराध करने में उसकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इस मायने में कोई चुनौती नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष कि मृतक की मृत्यु हत्या थी। [पैरा 25] [80-ई-एफ]

2.4 उच्च न्यायालय ने पाया है कि मृतक को लगी घातक चोटों की सामग्री से स्थापित किया गया था डॉक्टर द्वारा प्रमाणित पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (पीडब्लू 21)। इसके अलावा, पीडब्लू 21 राय दी कि मृतक के शरीर पर पाई गई चोट के लिए अपराध स्थल से बरामद दरांती को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि चोटें

उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू 21 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि चोटों पर चोटें लगी थीं और जिसके परिणामस्वरूप नसों के काटने से खून बह गया था। इसके अलावा, चोटों के विवरण से ही पता चलता है कि हड्डियां उजागर हुई थीं चोट के कारण। इसका मतलब है कि यह घाव का मामला था न कि घाव या सतही चोट का। अदालत आंख मूंदकर "घाव" अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती है, जब रिपोर्ट में वर्णित कट की चोट की प्रकृति और गहराई के खिलाफ खड़ा किया जाता है। हमले के दौरान दरांती का उपयोग, हत्या की मौत के बारे में अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष को मजबूत करता है और इसमें यह भी शामिल है कि चोटें जिसके परिणामस्वरूप मृतक की तत्काल मृत्यु हो गई। [पैरा 26] [80-जी-एच; 81 ए-सी]

3.1 उच्च न्यायालय ने यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया है कि आईपीसी की धारा 300 में दिए गए पांच अपवादों में से एक द्वारा मामला कैसे कवर किया जाएगा। जब तक मामला नहीं गिरता विनिर्दिष्ट अपवादों में से किसी एक के तहत, इसे आईपीसी की धारा 304 के पहले भाग या दूसरे भाग के तहत नहीं लाया जा सकता है। यहां तक कि अपीलार्थी-अभियुक्त का बचाव, जैसा कि सीआर.पी.सी की धारा 313 के तहत उसके बयान से स्पष्ट होता है, पूरी तरह से इनकार करने और गलत तरीके से फंसाने का है। वर्तमान मामले में आकर्षित आईपीसी की धारा 300 में कोई भी अपवाद नहीं है।। [पारस 28, 29] [82-ई; 83-बी-सी]

हरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 435: [1993] 2 एससीआर 137-पर निर्भर।

3.2 अभियुक्त (अपीलार्थी) ने उसकी हत्या कर दी। बेटी, जो गर्भावस्था के उन्नत चरण में थी और जिसे वह अकेले आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन

कारावास या मौत की सजा के लिए उत्तरदायी था। इस मामले की विशिष्ट तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, यह मौत की सजा देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। अपीलार्थी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। [पारस 29, 30] [83-डी-ई]

मामला कानून संदर्भ

(2016) 9 एससीसी 541	उस पर भरोसा करें	पैरा 13
[1971] 1 एससीआर 839	उस पर भरोसा करें	पैरा 20
2004 (7) एससीसी 257	उस पर भरोसा करें	पैरा 20
[1955] 2 एससीआर 94	उस पर भरोसा करें	पैरा 20
[1957] एससीआर 981	उस पर भरोसा करें	पैरा 22
[1993] 2 एससीआर 137	उस पर भरोसा करें	पैरा 28

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील. 631।/2012

कर्नाटक सर्किट बेंच उच्च न्यायालय में धारवाड़ के आपराधिक अपील संख्या 2259/2005 में पारित दिनांकित निर्णय और आदेश 03.06.2011 से।

सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस.जे. अमित (डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता के लिए), अधिवक्ता, अपीलार्थी के लिए।

देवदत्त कामत, एएजी, वी.एन. रघुपति, जावेदुर रहमान, प्रकाश जाधव, अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. यह आपराधिक अपील उत्पन्न होती है कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और अंतिम आदेशकी आपराधिक अपील संख्या 2259/2005 में दिनांक 3 जून, 2011। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत द्वारा बरी किए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है और इसके बजाय अपीलार्थी (अभियुक्त) को दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। भारतीय दंड संहिता, 1860 ('आईपीसी') की धारा 304, भाग । के तहत और उसे 10 (दस) साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई अपनी बेटी शिल्पा को मार डालना।

2. जब यह अपील 8 सितंबर, 2016 को सुनवाई के लिए ली गई, न्यायालय ने अपीलार्थी (अभियुक्त) को सजा बढ़ाने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। उस सूचना अपीलकर्ता द्वारा विधिवत जारी किया गया है।

3. इस अपील की ओर ले जाने वाली तथ्यात्मक परिस्थितियाँ इस प्रकार हैंः

ए. नाइक समुदाय के रवि कुमार (पीडब्लू 16) और लिंगायत समुदाय की शिल्पा में प्यार हो गया था। अलग-अलग जातियों से होने के कारण और शिल्पा के परिवार द्वारा उनकी शादी के विरोध के कारण, उन्होंने भागने का फैसला किया और 2002 में शादी कर ली। उन्होंने अपनी शादी कर ली2003 में उप-पंजीयक, होस्पेट के समक्ष पंजीकृत। आखिरकार, दंपति रवि कुमार (पीडब्लू 16), पीडब्लू 17 और पीडब्लू 18 के माता-पिता के साथ रहने के लिए अपने गाँव तारानगर लौट आए। जब इस शादी के बारे में शिल्पा के पिता को पता चला, तो आरोपी ने इसका कड़ा विरोध किया और कथित तौर पर कई मौकों पर पीडब्लू 16 और उनके परिवार को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनके परिवार के सम्मान को कम कर दिया है और वह अपनी बेटी को निचली जाति में शादी करने के लिए "खत्म" कर देगा।

बी. कथित घटना से पहले के दिनों में शिल्पा गर्भवती थी (लगभग नौ महीने)। वह अक्सर अपने निवास स्थान के पास सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करती थी, अक्सर अपनी सास (पीडब्लू 18) के साथ। दुर्भाग्यपूर्ण दिन यानी 3 अक्टूबर, 2003 को सुबह लगभग 8 बजे शिल्पा शौचालय जाना चाहता था। प्रासंगिक समय पर, पीडब्लू 18 अपने पति (पीडब्लू 17) के लिए 'रोटियाँ' तैयार कर रही थी जो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी। पीडब्लू 18 ने शिल्पा से कहा कि वह उस काम को पूरा करते ही उनके साथ शामिल हो जाएगी। अपना काम पूरा करने और हाथ धोने के बाद, पीडब्लू 18 सार्वजनिक शौचालय की ओर चलने लगी। जब वह एक हनुमंतप्पा के घर के पास थी, तो उसने शौचालय से शिल्पा के "अप्पा बेडा अप्पा" (पिता, नहीं, पिता) के रोने की आवाज सुनी। पीडब्लू18 शौचालय की ओर भागा। उसने अपीलार्थी (अभियुक्त) को खून से सना दरांती के साथ शौचालय से बाहर निकलते देखा। पीडब्लू18 को देखकर अपीलार्थी (अभियुक्त) ने उसे फेंक दिया। पास के गोबर के खाद के गड्ढे में दरांती डालें और भाग जाएं। हंगामा सुनकर पीडब्लू 1 से 4 जल्द ही मौके पर पहुंचे और पीडब्लू 18 के साथ सार्वजनिक शौचालय में घुस गए। उन्होंने शिल्पा को गर्दन में कट के साथ खून से लथपथ जमीन पर, ऊपर की ओर मुंह करके पड़ा पाया। पी. डब्ल्यू. 18 ने तब पी. एस. आई. (पी. डब्ल्यू. 24) के पास शिकायत दर्ज कराई, जिन्होंने तब एफ. आई. आर. दर्ज की। अपीलार्थी घटना के बाद फरार हो गया और अंततः 20 (बीस) दिनों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जाँच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी को अपनी बेटी शिल्पा की हत्या के लिए आरोप पत्र दायर किया गया और अदालत के समक्ष मुकदमा चलाने के लिए प्रतिबद्ध किया गया।

सी. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने विशेषज्ञों सहित 25 (पच्चीस) गवाहों के साक्ष्य का नेतृत्व किया। घटनास्थल पर पहुंचे चश्मदीद गवाह घटना पी. डब्ल्यू. 18 के

अपवाद के साथ प्रतिकूल हो गई, जिसकी गवाही को उच्च न्यायालय द्वारा सच्चा और विश्वसनीय पाया गया है।

डी. सत्र न्यायालय ने 28 फरवरी, 2005 के फैसले के माध्यम से आरोपी को इस आधार पर बरी कर दिया कि अपराध करने का आरोपी का केवल इरादा अपराध का निष्कर्ष दर्ज करने के लिए पर्याप्त नहीं था। सत्र न्यायालय ने पीडब्लू18 के साक्ष्य को खारिज कर दिया। इसने माना कि पीडब्लू 18 के साक्ष्य उनके पिछले बयान में सुधार से भरे हुए थे और अविश्वसनीय थे। इसके अलावा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य था अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।

ई. राज्य की अपील में, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली मामला कि आरोपी एक हताश पिता था क्योंकि उसकी बेटी की शादी रवि कुमार (पीडब्लू 16) से हुई थी, जो निचली जाति से था और अपराध करने का मकसद था। इसके अलावा, भले ही उसके साक्ष्य के दौरान पीडब्लू 18 द्वारा घटनाओं की थोड़ी अतिशयोक्ति की गई हो, उसे नजरअंदाज किया जा सकता है और यह कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर्याप्त था अभियुक्त को दोषी ठहराएँ। उच्च न्यायालय ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सीरोलॉजी रिपोर्ट पर भी भरोसा किया, जिसमें अन्य बातों के साथ कहा गया था कि शरीर पर खून के धब्बे हैं। दरांती मृतक के कपड़ों पर लगी दरांती से मेल खाती थी। अदालत ने अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया लेकिन आगे चला गया।

4. जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जब इस अपील की सुनवाई पहले के अवसर पर की गई थी, तो इस न्यायालय ने अपीलार्थी को कारण वाक्य की वृद्धि दर्शाकर नोटिस जारी किया था। इस अपील की सुनवाई की शुरुआत में और कारणदर्शक नोटिस पर, अपीलार्थी (अभियुक्त) की विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री सूरी ने अपील को वापस लेने

के लिए अदालत से अनुमति मांगी। वह प्रस्तुत करती है कि अभियुक्त द्वारा दोषसिद्धि के खिलाफ दायर वर्तमान अपील को वापस लेने के परिणामस्वरूप, वृद्धि के लिए नोटिस सजा (8 सितंबर 2016 को जारी) का स्वतः ही निपटारा हो जाएगा। जैसे ही हमने अपील वापस लेने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मामले के गुण-दोष पर हमें संबोधित किया।

5. गुण-दोष पर, सुश्री सूरी पहले प्रस्तुत करती हैं कि अभियोजन पक्ष अपराध करने में अभियुक्त के इरादे को साबित करने में विफल रहा है। बस। क्योंकि आरोपी अपनी बेटी की अंतर-जाति से नाखुश था विवाह, जो अपने आप में करने के उद्देश्य का अनुमान लगाने का आधार नहीं हो सकता है अपराध। इसके अलावा, जिन गवाहों ने आरोपी द्वारा पीडब्लू 16 और उसके परिवार को दी गई धमकियों के बारे में गवाही दी है, वे मुकर गए हैं। पीडब्लू 17 (रवि कुमार (पीडब्लू 16) के पिता) ने अपनी जिरह के दौरान कहा है कि आरोपी और उसके बीच अच्छे संबंध थे और यह सच नहीं था कि उसे मृतक को मारने की योजना बनाने वाले आरोपी के बारे में चेतावनी दी गई थी। पीडब्लू 18 (रवि कुमार की माँ (पीडब्लू 16)) का साक्ष्य, इस संबंध में एकमात्र दोषपूर्ण साक्ष्य है और इसकी पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है। पी.डब्ल्यू. 17 का साक्ष्य सुनी-सुनाई है। इसके अलावा, कोई नहीं गवाहों ने कथित अपराध करने के लिए अभियुक्त की ओर से किसी भी पूर्व योजना के बारे में बात की है। आरोपी ने कभी भी अपनी बेटी के साथ संबंध नहीं बनाए और न ही शादी के बाद गांव लौटने के बाद वह उससे मिला। अभियुक्त ने कभी भी पीडब्लू 16 और उसके परिवार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और न ही उसने अंर्तजातीय विवाह के संबंध में कोई पंचायत आयोजित करने की मांग की। आरोपी को पता नहीं चल सकता था कि मृतक कब शौचालय जाएगा और न ही उसे पता था कि घटना की तारीख को वह अकेली शौचालय जाएगी। अंत में, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था कि आरोपी ने मृतक की हत्या

के एकमात्र उद्देश्य के लिए दरांती (जो एक आम घरेलू वस्तु है) खरीदी थी। इस प्रकार, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि आरोपी की ओर से कथित अपराध करने का कोई इरादा था।

6. सुश्री सूरी आगे प्रस्तुत करती हैं कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पीडब्लू 18 के साक्ष्य पर आधारित है। भौतिक विरोधाभास हैं, पीडब्लू 18 द्वारा दिए गए साक्ष्य में विसंगतियों और चूक के कारण निचली अदालत ने यह दर्ज किया कि वह एक चश्मदीद गवाह नहीं थी और मामले पर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। सबूतों से पता चलता है कि पीडब्लू 18 ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए अपने मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया। सुश्री सूरी एफआईआर (एक्स पी-18) में इंगित करती हैं। घटना के तुरंत बाद दायर की गई, पीडब्लू 18 ने आरोप लगाया है कि उसने केवल आरोपी को हाथ में खून से सना दरांती लेकर शौचालय से बाहर निकलते देखा, जबकि अपने बयान में कहा कि उसने वास्तव में आरोपी को शिल्पा की गर्दन दरांती से काटते देखा था। यह स्पष्ट रूप से उसके मामले को सुधारने के लिए पीडब्लू 18 के प्रयास को दर्शाता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने इस तरह की विसंगति को "थोड़ी अतिशयोक्ति" करार देते हुए गलती की, जबकि यह वास्तव में एक भौतिक सुधार है। डॉक्टर (पीडब्लू 21) के साक्ष्य को पढ़कर इसकी पुष्टि होती है, जिसमें वह कहते हैं कि शिल्पा की मृत्यु का कारण गंभीर रक्तस्राव के कारण कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट था और यह कि मृत्यु रक्तस्राव के कारण वास्तविक हमले के कुछ मिनट बाद 5-10 हो सकता है। यह पीडब्लू 18 के कथन के विपरीत है कि जब वह शौचालय के पास पहुंची तो उसने आरोपी को शिल्पा पर हमला करते देखा। शौचालय और जहां से पीडब्लू 18 ने कथित तौर पर घटना को देखा था, उसके बीच की दूरी को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि जब तक पीडब्लू 18 शौचालय पहुंची, तब तक शिल्पा की खून बहने से मौत हो गई होगी। यह केवल यह साबित करता है कि पीडब्लू 18 ने वास्तव में आरोपी

को अपराध करते हुए नहीं देखा था क्योंकि जब पीडब्लू 18 मौके पर पहुंची तो शिल्पा पहले ही मर चुकी थी और कथित अपराध कुछ समय पहले हुआ होगा। पीडब्लू 18 ने अपने साक्ष्य में इस विसंगति को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा कि शिल्पा हमले के बाद भी जीवित थी और उसने उसे एक टम्बलर में कुछ पानी दिया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। साक्ष्य देने से पहले इस टम्बलर की उपस्थिति का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। यह बदलाव पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, हनुमथप्पा के घर से दूरी, जहाँ से पीडब्लू 18 ने कथित रूप से घटना देखी थी या मृतक के रोने की आवाज सुनी थी, शौचालय से कम से कम 1 फरलोंग (200 मीटर) दूर थी। पीडब्लू18 संभवतः आरोपी को इतनी दूर से अपराध करते हुए नहीं देख सकता था। यहां तक कि यह तथ्य कि पीडब्लू18 ने मृतक की चिल्लाहट "अप्पा बेडा अप्पा" या "पिता, नहीं, पिता" अविश्वसनीय है। जबकि, पीडब्लू 16 सबूत में बताता है कि पीडब्लू 18 ने उसे बताया कि मृतक चिल्लाया "ओह मैं गर्भवती हूँ। कृपया मेरे साथ कुछ भी न करें", इस प्रकार स्पष्ट रूप से पी. डब्ल्यू-18 के साक्ष्य में विसंगति का संकेत देता है। अंत में, पीडब्लू 18 का सबूत कि जब उसने आरोपी को अपराध करते देखा तो वह अकेली थी, पीडब्लू 16 की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट द्वारा सीधे तौर पर विरोधाभासी है। सबूत जब यह कहता है कि घटना के समय, शौचालय के बाहर एक कतार होगी। इस प्रकार, पी डब्ल्यू- 18 की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है और बिना पुष्टि के स्वीकार नहीं की जा सकती है।

7. सुश्री सूरी ने आगे कहा कि पी डब्ल्यू-17 के साक्ष्य से पता चलेगा कि केवल संदेह के आधार पर आरोपी के खिलाफ एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई थी पीडब्लू 18 का। इसके अतिरिक्त, आरोपी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रुद्रप्पा के परामर्श से पीडब्लू 18 द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि घटना सुबह 8

बजे हुई थी, लेकिन प्राथमिकी केवल 10:30 एएम के आसपास दर्ज की गई और सुबह 11:30 बजे से 1:30 पीएम के बीच हुई पूछताछ। इसके अलावा, पीडब्लू 18 का सबूत कि पुलिस ने पहली बार में प्राथमिकी दर्ज नहीं की, पीडब्लू 25 द्वारा सीधे तौर पर विरोधाभासी है, जो इसमें कहा गया है कि वास्तव में पहली बार में ही एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी। यह मानने का कारण है कि पीडब्लू 18 ने प्राथमिकी दर्ज करने से पहले रुद्रप्पा से परामर्श करने में समय लिया। पीडब्लू18 का साक्ष्य पूरी तरह से अविश्वसनीय है। पीडब्लू 18 के कहने पर दर्ज प्राथमिकी में आरोप संदेह और प्रेरित हैं।

8. सुश्री सूरी आगे प्रस्तुत करती हैं कि चोटों का विवरण मृतक के शरीर पर घाव थे। अपीलार्थी द्वारा अपराध करने में कथित रूप से इस्तेमाल की गई दरांती से यह संभव नहीं था। इसके अलावा, प्रतिपरीक्षा के दौरान, चिकित्सा रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर ने कहा कि इस तरह के घाव खुरदरी सतह पर गिरने के कारण हो सकते हैं। डॉक्टर ने उस धारदार हथियार जैसे दरांती को भी हटा दिया घावों का कारण बनता है लेकिन वर्तमान मामले में, चोट एक घाव था। दरांती जैसे नुकीले हथियार से होने वाली चोट हमेशा तिरछी होती है न कि लंबवत। विशेष रूप से, मृतक पर पाई गई चोट को तिरछी चोट नहीं बताया गया था। इसके अलावा, मेडिकल रिपोर्ट में आरोपी की उंगलियों के निशान दरांती पर नहीं पाए गए, जिससे यह संदेह पैदा होता है कि क्या उक्त दरांती का इस्तेमाल आरोपी द्वारा बहुत कम किया गया था। इसके अलावा, पीडब्लू18 अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताती है कि उसने आरोपी के कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं देखा और न ही उसने खुद अपने कपड़ों पर कोई खून का धब्बा देखा। अगर आरोपी ने शिल्पा को चोट पहुँचाने के लिए दरांती का इस्तेमाल किया होता, तो जाहिर है कि उसके कपड़ों पर खून का छिड़काव होता, लेकिन पी. डब्ल्यू. 18 खुद इस संभावना को नकारती है।

9. सुश्री सूरी ने आगे कहा कि सीरोलॉजी रिपोर्ट में "बी" समूह से संबंधित दरांती पर रक्त का पता चलता है, लेकिन इस बारे में कोई सबूत नहीं है। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड करें कि या तो पीड़ित का खून या आरोपी का खून "बी" समूह का था। अभियोजन पक्ष द्वारा इसकी व्याख्या नहीं की गई है। इसके अलावा, विचाराधीन दरांती को किसी अन्य दरांती से अलग करें। चूंकि पीडब्लू 12 और 13 शत्रुतापूर्ण हो गए थे, इसलिए एकमात्र पहचान कारक मुहर बचा था और यह तथ्य कि दरांती को उचित अभिरक्षा में रखा गया था, स्थापित नहीं किया गया है। इसे भी चुनौती दी गई है क्योंकि दरांती को 3 अक्टूबर, 2003 को जब्त कर लिया गया था लेकिन भेज दिया गया था। 16 अक्टूबर, 2003 को फोरेंसिक प्रयोगशाला में, बीच की अवधि के दौरान इसके स्थान के बारे में एक फुसफुसाहट के बिना। इसके अलावा, दरांती को एक अनधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रयोगशाला में भेजा गया था जिसकी जांच नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, जिस सीरोलॉजिस्ट ने दरांती प्राप्त की थी, उसकी यह साबित करने के लिए जांच नहीं की गई थी कि उसे जो दरांती मिली थी, वह वही थी जिस पर एस. एच. ओ. की मुहर थी। आगे की जांच के लिए पी. डब्ल्यू. 21 को दरांती भेजे जाने के बाद, पी. डब्ल्यू. 21 ने उसे खोला जब वह ओपीडी में अकेले थे और फिर उसे अपनी व्यक्तिगत मुहर से सील कर दिया। साक्ष्य के दौरान गवाह द्वारा इस व्यक्तिगत मुहर की पहचान नहीं की गई थी। इस प्रकार, उच्च न्यायालय सीरोलॉजी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकता था क्योंकि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दरांती पीडब्लू 18 द्वारा पहचानी गई दरांती वही थी जिसे पुलिस ने जब्त किया था। इस प्रकार, यह उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका कि आरोपी ने दरांती का इस्तेमाल किया था या दरांती शिल्पा की मृत्यु का कारण बनने वाला उपकरण था।

10. सुश्री सूरी यह भी प्रस्तुत करती हैं कि घटना के बाद मृतक के कपड़े जब्त कर लिए गए थे लेकिन अस्पताल में सील नहीं किए गए थे। पी. डब्ल्यू. 19 द्वारा

कपड़ों को पुलिस थाने लाया गया और निरीक्षक, पी. डब्ल्यू. 25 द्वारा पंच पी. डब्ल्यू. 14 के साथ सील कर दिया गया। हालाँकि, पीडब्लू 14 के साक्ष्य से पता चलता है कि वह उक्त पंचनामे की सामग्री नहीं जानते थे।

11. सुश्री सूरी प्रस्तुत करती हैं कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था क्योंकि सत्र न्यायालय ने किया था अभिलेख पर पूरे साक्ष्य पर विचार किया। भले ही उच्च न्यायालय की राय थी कि साक्ष्य से दो उचित विचार संभव थे अभिलेख पर, यह दर्ज करने में विफल रहा है कि सत्र न्यायालय का निष्कर्ष कैसे असमर्थनीय था।

12. सारांश में, सुश्री सूरी प्रस्तुत करती हैं कि पीडब्लू 18 के साक्ष्य की अवहेलना की जानी चाहिए। जिस मामले में, कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है अपराध करने में अभियुक्त की संलिप्तता स्थापित करना। उपलब्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य कमजोर है और अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला को पूरा करने में विफल रहे। अभियुक्त का अपनी बेटी की हत्या करने का इरादा उचित संदेह से परे स्थापित नहीं हुआ है। इस प्रकार, अभियुक्त को सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नेत्र साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य का आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार किया जाना चाहिए।

13. जवाब में श्री कामत प्रस्तुत करते हैं कि विचाराधीन अपराध ऑनर किलिंग का एक स्पष्ट मामला है और विकास यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) 9 एससीसी 541) इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ऑनर किलिंग के मामले में सबसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

14. श्री कामत निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। वह प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त का उद्देश्य महत्वपूर्ण होगा

अपने अपराध को साबित करना। यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है कि आरोपी का अपराध करने का इरादा था। श्री कामत ने पीडब्लू 18 के साक्ष्य से बताया कि पीडब्लू 16 और शिल्पा की शादी के बाद आरोपी कभी भी पीडब्लू 18 के घर पर दंपति से मिलने नहीं आए क्योंकि वे निचली जाति के थे। इसके अलावा, आरोपी ने बार-बार पीडब्लू 16 और 17 को धमकी दी कि वह उसकी बेटी को खत्म कर देगा क्योंकि उसने परिवार का नाम बर्बाद कर दिया था। पी. डब्ल्यू. 18 हमेशा शिल्पा के साथ रहता था जब वह शौचालय जाती थी क्योंकि उसे डर था कि आरोपी उसकी धमकियों का फायदा उठाएगा। यह सब दर्शाता है कि अभियुक्त के कार्यों के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य था। उच्च न्यायालय ने पाया है कि आरोपी हताश था क्योंकि उसकी बेटी ने पी. डब्ल्यू. 16 से शादी करने के लिए उसे अचानक छोड़ दिया। नतीजतन, घटना के दिन बोतलबंद भावना और उथल-पुथल मच गई। यदि आरोपी ने अपराध नहीं किया होता, तो वह घटना के बाद 20 (बीस) दिनों तक फरार नहीं होता।

15. श्री कामत ने आगे कहा कि पी. डब्ल्यू. 18 के साक्ष्य में विसंगति/सुधार को खारिज करने में उच्च न्यायालय सही था। अभियुक्त को अपनी बेटी पर हमला करते हुए देखा। भले ही पीडब्लू 18 के साक्ष्य में सुधार को खारिज कर दिया जाए, परिस्थितियों की श्रृंखला स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध से संबंध स्थापित करती है। पीडब्लू 18 के साक्ष्य के अलावा, उच्च न्यायालय ने अपराध करने के लिए अभियुक्त के मजबूत उद्देश्य सहित परिस्थितियों की श्रृंखला पर भरोसा किया है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सकती है।

16. श्री कामत ने आगे कहा कि बचाव पक्ष ने पीडब्लू18 के इस साक्ष्य को चुनौती नहीं दी है कि उसने आरोपी को जनता से बाहर निकलते देखा था हाथ में खून

से सना दरांती लिए शौचालय और उसे पास में फेंक दिया पीडब्लू 18 को देखकर गोबर का गड्ढा। पीडब्लू 18 का सबूत है कि वह सार्वजनिक शौचालय के ठीक पीछे, हनुमंतप्पा के घर के पास थी जब उसने शिल्पा के बारे में सुना चिल्लाते हुए, चुनौती नहीं दी गई है। पीछे हनुमंतप्पा का घर था। सार्वजनिक शौचालय और 1 फरलोंग की दूरी पर नहीं। इसलिए, पीडब्लू18 का सबूत, कि उसने शिल्पा को चिल्लाते हुए सुना और आरोपी को खून से सना दरांती के साथ शौचालय से बाहर आते देखा, विश्वसनीय सबूत है।

17. श्री कामत ने आगे कहा कि बचाव पक्ष पीडब्लू18 के इस बयान को चुनौती देने में विफल रहा है कि उसने आरोपी को दरांती के साथ देखा था। उसका हाथ और यह कि उसने इसे पास के गोबर के गड्ढे में फेंक दिया और भाग गया, इस तथ्य की पुष्टि खून से सना दरांती की पुनर्प्राप्ति से होती है। यहां तक कि निचली अदालत ने भी घटनास्थल से खून से सना दरांती जब्त करने के अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार कर लिया है, जैसा कि साबित हुआ है।

18. श्री कामत ने तब अभियुक्त की इस दलील का खंडन किया कि मृतक पर लगने वाले घावों की प्रकृति एक कारण से नहीं हो सकती थी सिकल। श्री कामत ने हमें डॉक्टर के साक्ष्य (पीडब्लू21) के माध्यम से लिया और बाहरी चोटों के विवरण की ओर इशारा कियाः

> "1) लगभग 6 सेमी x3x3 सेमी मापने वाले पूर्व भाग पर बाईं ओर गर्दन पर घाव, खून बह गया था, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को देखा गया था और नसों को चोट लगी थी और घाव से खून बह गया था।

2) बाएँ कंधे के जोड़ पर ऊपरी भाग पर लगभग 7x3x8 सेमी घाव, घाव से कोई रक्तस्राव नहीं।

3) दाहिने गाल पर घाव, लगभग 2 सेमी x 0.5 सेमी, खून नहीं बह रहा है।

4) दाहिने अग्र-भुजा पर निचले 13 पर पार्श्व पक्ष पर लगभग 5 सेमी x 3 सेमी x 2 सेमी घाव, हड्डियाँ और कंडरा उजागर हो जाते हैं। घाव से खून बह गया था।"

श्री कामत प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि मृतक को लगी चोट एक घाव नहीं था जैसा कि डॉक्टर ने शिथिल रूप से कहा था, बल्कि एक गहरा और कटा हुआ घाव था। श्री कामत प्रस्तुत करते हैं कि एक घाव बलपूर्वक लगाने के कारण हो सकता है शरीर की सतह पर या ऊंचाई से गिरने के कारण कुंद हथियार। इसके विपरीत, एक तीखा घाव तब होता है जब एक तेज और नुकीला किनारे वाले हथियार या उपकरण द्वारा नरम ऊतक को मारा या दबाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप रक्तस्राव होता है। वर्तमान मामले में, साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि घाव गहरा था और मृतक की अंतर्निहित नसें, नसें और हड्डियां थीं, देखा जा सकता था। यह अपने आप में यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि मृतक पर लगाया गया घाव एक कटा हुआ घाव था और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में दरांती द्वारा लगाया गया था सवाल करते हैं। इसके अलावा, डॉक्टर ने बयान दिया है कि विचाराधीन दरांती से लगी चोटों के कारण मृतक की मौत हो सकती है।

19. श्री कामत ने आगे कहा कि साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि दरांती पर पाया गया रक्त रक्त समूह से मेल खाता है। मृतक के कपड़े, भले ही रक्त के प्रकार को साबित करने के लिए कोई रिपोर्ट न हो मृतक का, यह सबूत कि दरांती पर खून वही

था जो शिल्पा के कपड़ों पर पाया गया था, उचित संदेह से परे साबित करता है कि गड्ढे में पाई गई दरांती का उपयोग अपराध करने में किया जाता था। वह प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाए और सजा बढ़ाने के लिए नोटिस को पूर्ण बनाया जाए।

20. अभियुक्त को 8 सितंबर, 2016 के आदेश के अनुसार, धारा 386 के तहत अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता के लिए उत्तरदायी मूल कार्यवाहियों को इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाए या इसके साथ पढ़ा जाए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआर पी.सी.) की धारा 397 और 401 और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण अधिकारिता। यह शो सजा बढ़ाने के लिए कारण सूचना खेडू मोहटन और अन्य बनाम राज्य बिहार 1970 (2) एससीसी 450 में कानून के स्पष्टीकरण के अंतर्निहित सिद्धांत पर आगे बढ़नी चाहिए। उस मामले में, उच्च न्यायालय के समक्ष बरी किए जाने के खिलाफ अपील के लंबित रहने के दौरान शिकायतकर्ता की मृत्यु हो गई और इसलिए, अभियुक्त द्वारा यह आग्रह किया गया कि उक्त अपील को समाप्त कर दिया गया है। इस न्यायालय ने अभियुक्त की उस याचिका को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि अपील केवल अभियुक्त की मृत्यु। अदालत ने तब कहा कि एक बार अपील बरी किए जाने के विरुद्ध उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है, यह उच्च न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अपीलार्थी उस पर मुकदमा चलाने का विकल्प नहीं चुनता है या किसी न किसी कारण से उस पर मुकदमा चलाने में असमर्थ है, उसी पर निर्णय करे। दोनों को सुनने के बाद इस न्यायालय द्वारा जारी सजा में वृद्धि के लिए स्वतः संज्ञान कारण नोटिस के लिए एक ही सादृश्य लागू करना। पक्षकार, यह इस न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इस तथ्य की परवाह किए बिना कि अभियुक्त इसके खिलाफ अपनी अपील पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता है, उसी पर निर्णय करे। इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी उचित

हो सकता है। देव नारायण मंडल बनाम यू.पी. 2004 (7) एससीसी 257 (पैरा 5) की स्थिति रिपोर्ट किए गए अनुच्छेद 5 में निर्णय, इस न्यायालय ने राय दी कि चूंकि सजा बढ़ाने का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए यह कानून की दृष्टि से उचित है कि अदालत को मामले के गुण-दोष के आधार पर भी आरोपी की सुनवाई करनी चाहिए, भले ही आरोपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष गुण-दोष के आधार पर अपनी अपील नहीं की थी। उस मामले में, अभियुक्त ने इस न्यायालय के समक्ष कम दोषसिद्धि के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी थी। यह ठीक है कानून में स्थिति स्थापित की कि सजा बढ़ाने के लिए नोटिस की सुनवाई के दौरान, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पायलट यू.जे.एस. चोपड़ा बनाम बॉम्बे राज्य 1955 (2) एससीआर 94 (3 न्यायाधीश) में अभिनिर्धारित किया गया था। अभियुक्त को यह भी अधिकार होगा कि वह अपनी सजा को क्यों नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, इसका कारण बताते हुए अपनी दोषसिद्धि के खिलाफ कारण बताए। इस स्थिति को महसूस करते हुए, अपीलार्थी के वकील ने अपीलार्थी को बरी करने के लिए जोरदार तर्क दिया।

21. यह हमें अपीलार्थी के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए। अपराध के निष्कर्ष के गुण-दोष पर ले जाता है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी के विरुद्ध साक्ष्य की पर्याप्तता के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष कमजोर आधारों पर आधारित है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पूरे साक्ष्य का नए सिरे से विश्लेषण किया और पाया कि भले ही अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से एकमात्र गवाह (पीडब्लू 18) के साक्ष्य पर आधारित होगा, फिर भी अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए जो उसके साक्ष्य की पुष्टि करते हैं, अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष निकाला जा सकता है। सुरक्षित रूप से दर्ज किया गया। इसमें, अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू 18 की परिस्थिति स्थापित की है। जिसमें उसने आरोपी (अपीलार्थी) को सार्वजनिक शौचालय से खून से सने दरांती के साथ बाहर आते हुए और पीडब्लू 18 को

देखने के बाद उक्त दरांती को पास के गोबर के गड्ढे में फेंकते हुए देखा था। उच्च न्यायालय ने माना कि पीडब्लू 18 का साक्ष्य अन्यथा सच्चा और विश्वसनीय था। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त के आचरण और अपराध करने के उसके मजबूत उद्देश्य के बारे में साक्ष्य को ध्यान में रखा है, जैसा कि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों द्वारा खुलासा किया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दरांती पर पाए गए रक्त के धब्बों के साक्ष्य रक्त समूह बी से मेल खाते हैं। पंचनामा (प्रदर्श पी-6) पीडब्लू 25 द्वारा साबित किया गया; वस्तुओं की जब्ती (मॉस- 4 से 6) पीडब्लू 25 द्वारा साबित किया गया; दरांती का जब्ती पंचनामा (प्रदर्श- पी 8) पीडब्लू 18 और 25 द्वारा साबित किया गया; खून से सने कपड़ों की जब्ती और चप्पल की जोड़ी मृतक शिल्पा (प्रदर्श पी-9) पीडब्लू 25, 14 और 19; द्वारा साबित किया गया; और पीडब्लू 21 और पीडब्लू 25 के साक्ष्य जिन्होंने पंचनामा (एक्सएच) को साबित किया। 21) के बारे में पीडब्लू 21 डॉ. रामासेट्टी को दरांती दिखाना।

22. उच्च न्यायालय ने माना कि घटनाओं की श्रृंखला और वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य एआईआर 1957 एससी 614 में उच्चतम न्यायालय द्वारा बताए गए सिद्धांत को लागू करना। उच्च न्यायालय ने पी डब्ल्यू 21 के साक्ष्य और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर भी विचार किया ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि बरामद की गई दरांती का उपयोग अपराध करने के लिए किया गया था और शिल्पा को हुई चोट इस तरह के हथियार के उपयोग से संभव थी और जिसके परिणामस्वरूप उसकी मौत हो गई थी। तदनुसार, उच्च न्यायालय अपीलार्थी को संदेह का लाभ देकर बरी करने के निचली अदालत के निष्कर्ष से सहमत नहीं था। इसके बजाय, उच्च न्यायालय ने प्रतिशोध और हताशा के कारण अपनी बेटी शिल्पा (जो प्रासंगिक समय पर गर्भावस्था के उन्नत चरण में थी) की हत्या के लिए अपीलार्थी के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष दर्ज किया। उच्च न्यायालय, हालाँकि, अपीलार्थी आई.पी.सी. की धारा 304 भाग । के

तहत इस निष्कर्ष पर दोषी ठहराए जाने के लिए आगे बढ़े कि अपराध अपीलार्थी द्वारा किया गया था, जो एक हताश पिता था क्योंकि उसकी बेटी ने निचली जाति के एक लड़के से शादी की थी, जिसे वह रोक नहीं सका था और घटना के दिन उस निराशा को भड़काया था। जब उसने अपनी ही बेटी पर हमला किया था। इस दृष्टिकोण की शुद्धता पर थोड़ी देर बाद विचार किया जाएगा।

23. हम सबसे पहले दोष के निष्कर्ष की शुद्धता की जांच करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित। इससे पहले, हमें अपीलार्थी को संदेह का लाभ देने के लिए निचली अदालत के दृष्टिकोण का विज्ञापन करना चाहिए। मुकदमे की सुनवाई अदालत ने पाया कि पूछताछ पंचनामा (प्रदर्श पी-6) पीडब्ल्यू 25 द्वारा साबित किया गया था। अनुच्छेद (मोस 4 से 6) के संबंध में जब्ती पंचनामा (प्रदर्श पी-7) देखें, अर्थात्, रक्त से सना हुआ मिट्टी, सादा मिट्टी और 6 चूड़ी के टुकड़े, पी. डब्ल्यू. 25 द्वारा साबित किए गए हैं। द सीज़र पंचनामा (एक्स. पी-8) सार्वजनिक शौचालय के पास खाद के गड्ढे से खून से सना दरांती के बारे में पीडब्लू 25 और पीडब्लू 18 द्वारा साबित किया गया है। निचली अदालत ने यह भी पाया कि अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि वस्तुओं की जब्ती (मो. 1 से 3) पंचनामा के तहत पी-9) मृत शिल्पा का शरीर पर क्रमशः नाइटी, छोटे कोट और हवाई चप्पल की जोड़ी पाई गई। ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि खून से सना दरांती की सीलिंग (एक्सएच। पी-21) और पीडब्लू 21 द्वारा इसकी पहचान पीडब्लू 21 और 25 के साक्ष्य से साबित हुई है। निचली अदालत को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य, विशेष रूप से पीडब्लू 18, 16 और 17 में कोई कमजोरी नहीं मिली, कि अपीलकर्ता अपनी बेटी शिल्पा के साथ पीडब्लू 16 से शादी करने के लिए झगड़ रहा था और उसे खत्म करना चाहता था। हालाँकि, निचली अदालत ने राय दी कि भले ही इन सभी परिस्थितियों को होना था सिद्ध के रूप में स्वीकार किया गया, तब भी वे एक रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध का

पता लगाना। क्योंकि, पीडब्लू18 का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने नोट किया कि पीडब्लू 18 एकमात्र गवाह था जो दावा किया कि उसने आरोपी को हाथ में खून से सना दरांती लेकर सार्वजनिक शौचालय से बाहर आते हुए देखा और उसे पास के गोबर के गड्ढे में फेंक दिया। हालाँकि, उस साक्ष्य की किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा पुष्टि नहीं की गई थी। इसके अलावा, पीडब्लू18 ने आरोपी (अपीलार्थी) को वास्तव में अपनी बेटी शिल्पा (पीडब्लू18 की बहू) पर हमला करते हुए देखकर गवाही देकर अपने बयान में सुधार या अतिशयोक्ति की। इस पर इस कारण से, पी. डब्ल्यू. 18 के साक्ष्य को निचली अदालत ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। निचली अदालत के इस दृष्टिकोण को उच्च न्यायालय ने कमजोर पाया है। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू 18 के साक्ष्य की उचित जांच पर उसने अपीलार्थी के खिलाफ निर्णायक परिस्थिति साबित कर दी कि उसने उसे सार्वजनिक शौचालय से बाहर निकलते हुए देखा था, जहाँ उसकी बेटी शिल्पा मृत पाई गई थी, उसके हाथ में खून से सना दरांती था और पीडब्लू 18 को देखकर और मौके से भागने के बाद उस दरांती को पास के गोबर के गड्ढे में फेंक दिया था।

24. इसलिए, विवादास्पद प्रश्न यह है कि क्या मूल्यांकन के संबंध में निचली अदालत का दृष्टिकोण या उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण पीडब्लू 18 का प्रमाण सही है। पीडब्लू 18 के साक्ष्य को देखने के बाद, हमें उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि पीडब्लू 18 के पूरे संस्करण को असत्य नहीं माना जा सकता है। उसका सबूत कि उसने सार्वजनिक शौचालय "अप्पा बेडा अप्पा" से अपनी बहू शिल्पा के रोने की आवाज सुनी थी और उसके बाद उसने आरोपी को हाथ में खून से सना दरांती लेकर सार्वजनिक शौचालय से बाहर आते हुए और उस दरांती को पास के गोबर के गड्ढे में फेंकते हुए देखा, जब उसने पीडब्लू 18 को देखा तो उसने उसे रुकने और फिर मौके से भागने के लिए कहा, विश्वसनीय है और सत्यवादी। पीडब्लू18

के इस संस्करण पर संदेह करने का कोई ठोस कारण नहीं है। उसी को स्वीकार करने पर, यह आवश्यक रूप से होगा कि केवल आरोपी ही शिल्पा की हत्या के लिए जिम्मेदार था, जो तथ्य उसके ऐसा करने के मजबूत उद्देश्य से पुष्ट होता है। इसके अलावा, पीडब्लू 18 का यह संस्करण पुष्ट है। रक्त के धब्बों की जब्ती सहित अन्य अभियोजन साक्ष्य से घटनास्थल से दरांती और दरांती पर और मृतक शिल्पा के कपड़ों पर रक्त समूह "बी" का मिलान। उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष और विशेष रूप से अपीलार्थी (अभियुक्त) के खिलाफ अपराध का निष्कर्ष सही दृष्टिकोण है। हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निचली अदालत ने पीडब्लू 18 के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए तुच्छ कारण दिए हैं। वादिवेलु थेवर (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में बताए गए सिद्धांत को लागू करने में भी उच्च न्यायालय सही था। अभिनिर्धारित किया है कि अभियोजन पक्ष कुछ स्थितियों में एकल एस के आधार पर अपने मामले को समाप्त कर सकता है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित पर भरोसा कियाःउक्त निर्णय के परिणामः

"(11) इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि एक हत्या के मामले में, किसी भी मामले में, किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए गवाहों की आवश्यकता होगी। विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए यह आवश्यक नहीं होगा, किसी भी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना। इंग्लैंड में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, पृष्ठ 1100 और 1101 पर सरकार के साक्ष्य कानून-9 वें संस्करण में निर्धारित कई क़ानून हैं। एकल गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि का निषेध करना। भारतीय विधानमंडल ने किसी को भी निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है धारा 134 में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के ऐसे अपवाद। ऊपर उद्धृत किया गया। इस खंड में एक अच्छी तरह से

मान्यता प्राप्त कहावत है कि 'साक्ष्य को तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए'। हमारे विधानमंडल ने इस तथ्य को वैधानिक मान्यता दी है कि न्याय के प्रशासन में बाधा आ सकती है। यदि कोई विशेष गवाहों की संख्या पर जोर दिया जाना था। ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई अपराध केवल एक की उपस्थिति में किया गया हो। गवाह, उन मामलों को छोड़कर जो असामान्य घटना के नहीं हैं जहां अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि विधानमंडल इस पर जोर देता है। गवाहों की बहुलता, ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती है, बिना दंड के चले जाएँ। यही वह जगह है जहाँ पीठासीन न्यायाधीश का विवेक कार्य में आता है। अतः मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए। एकल गवाह जिसकी गवाही या तो होनी चाहिए स्वीकार या अस्वीकृत। यदि न्यायालय द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। यद्यपि एक अभियुक्त व्यक्ति का अपराध एक गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है, एक अभियुक्त की बेगुनाही व्यक्ति को एकल गवाह की गवाही पर स्थापित किया जा सकता है, भले ही अभियोजन पक्ष के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए काफी संख्या में गवाह सामने आ सकते हैं। इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि अदालत का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से। आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

श्रेणियाँ, अर्थात्:

(1) पूरी तरह से विश्वसनीय

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(12) सबूत की पहली श्रेणी में, अदालत को होना चाहिए किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है-यह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकता है या बरी कर सकता है, यह निंदा या रुचि के संदेह से ऊपर, क्षमता या अधीनता में पाया जाता है। दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में समान रूप से कोई कठिनाई नहीं होती है। यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि अदालत को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है। गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक और खतरा है। एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से उत्साहजनक होंगे। गवाहों का अधीनता। ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध हो। स्वाभाविक रूप से न्यायालय को इस तरह की गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा और यदि यह संतुष्ट है कि साक्ष्य विश्वसनीय होता है और उन सभी कलंकों से मुक्त होता है जो मौखिक गवाही को संदेह के लिए खुला रखते हैं, इस तरह की गवाही पर कार्रवाई करना इसका कर्तव्य बन जाता है। कानून की

रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां अदालत को इस पर निर्भर रहना और कार्य करना पड़ता था अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकल गवाह की गवाही। इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन अपराधों के मामलों में या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपनी प्रकृति से, संदिग्ध है, जो अपराध में भागीदार है। जहां इस तरह के कोई असाधारण कारण नहीं हैं, यह अदालत का कर्तव्य बन जाता है कि वह दोषी ठहराए, यदि यह संतुष्ट हो कि एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है। इसलिए हमारे पास पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है अभियोजन पक्ष से।''

वर्तमान मामले में, पीडब्लू 18 के साक्ष्य की पुष्टि अन्य परिस्थितियों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी का न केवल अपनी बेटी को मारने का मजबूत मकसद था, बल्कि वह ऐसा करने के लिए जिम्मेदार था और शिल्पा की मौत के लिए किसी और के जिम्मेदार होने की संभावना को छोड़ देता है। के लिए वकील इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी ने हमें पीडब्लू 18 के साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज करने के लिए मनाने का प्रयास किया, जैसा कि निचली अदालत ने किया है। फिर भी हम वे उस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हम पाते हैं कि पीडब्लू18 के साक्ष्य की प्रभावशीलता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, अन्य सिद्ध परिस्थितियों और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एकमात्र संभावित दृष्टिकोण प्रतीत होता है और मामले में सही दृष्टिकोण है। अपीलार्थी के तर्क को अस्वीकार करने में हमें कोई संकोच नहीं है। जब्ती पंचनामा और वस्तुओं की बरामदगी पर अविश्वास करना। क्योंकि, यहाँ

तक कि निचली अदालत ने भी राय दी है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा भी यही साबित किया गया है।

25. अपीलार्थी को इस निष्कर्ष पर संदेह है कि अपराध करने में उसकी संलिप्तता का संकेत देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। इस मायने में निचली अदालत के इस निष्कर्ष को कोई चुनौती नहीं है कि शिल्पा की मौत हत्या थी। अपराध की खोज पर विचार करना उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित और हमारे द्वारा बरकरार रखा गया, यह अनिवार्य रूप से इस बात का पालन करना चाहिए कि यह गैर-इरादतन हत्या का मामला है। पीडब्लू 21 की राय को चुनौती देने का प्रयास किया गया था, कि चोटें नहीं हो सकती हैं। अपराध स्थल से बरामद दरांती को जिम्मेदार ठहराया गया और किसी भी मामले में, चोटों को शिल्पा की मौत के इरादे से नहीं लगाया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष इसी तरह के तर्क पर विचार किया है, लेकिन इसे नकार दिया है और हमारी राय में यह सही है।

26. उच्च न्यायालय ने पाया है कि घातक चोटों को मृतक शिल्पा की पुष्टि डॉक्टर (पीडब्लू 21) द्वारा साबित की गई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट की सामग्री से हुई थी। इसके अलावा, पीडब्लू 21 ने राय दी कि शिल्पा के शरीर पर पाई गई चोट का कारण बरामद की गई दरांती गंदी डोड्डाबासप्पा @गांधी बासवराज बनाम को माना जा सकता है। अपराध स्थल से। उन्होंने आगे कहा कि चोटें उनकी मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। हालाँकि अपीलार्थी के वकील ने हमें यह समझाने के लिए बहुत मेहनत की कि पीडब्लू 21 द्वारा चोटों का विवरण केवल घाव थे, लेकिन पंचनामा, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पीडब्लू 21 के साक्ष्य की बारीकी से जांच करने पर, यह है यह स्पष्ट है कि चोटें लगी हुई थीं और जिसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ नसों के काटने के कारण खून आना। इसके अलावा, चोटों के विवरण से ही पता चलता है कि चोट के कारण

हड्डियां उजागर हुई थीं। इसका मतलब है यह कटा हुआ घाव का मामला था न कि घाव या सतही चोट का। अदालत आंख मूंदकर "घाव" अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती है, जब रिपोर्ट में वर्णित कट की चोट की प्रकृति और गहराई के खिलाफ खड़ा किया जाता है। हमले के दौरान दरांती का उपयोग, हत्या की मौत के बारे में निचली अदालतों द्वारा किए गए निष्कर्ष को मजबूत करता है और इसमें यह भी शामिल है कि चोटों के परिणामस्वरूप शिल्पा की तत्काल मौत हो गई थी।

27. मामले के समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए, हम विचार कर रहे हैं राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त (अपीलार्थी) के खिलाफ दर्ज किए गए अपराध का निष्कर्ष स्पष्ट नहीं है और इसके लिए कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

28. अगला सवाल हैः क्या द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा 304 भाग । के तहत उच्च न्यायालय को कायम रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 20, 21 और 22 में उस मुद्दे पर विचार किया जो इस प्रकार पढ़ता हैः

> "20. यदि न्यायालय सत्य के बारे में आश्वस्त है। अभियोजन की कहानी, दोषसिद्धि का पालन करना होगा। सवाल यह है कि वाक्य निर्धारित किया जाना चाहिए, के संदर्भ में नहीं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की मात्रा या चरित्र अभियोजन मामले के समर्थन में अभियोजन लेकिन के साथ इस तथ्य का संदर्भ कि क्या कोई विस्तार है अपराध। यदि न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसे हैं। परिस्थितियों को कम करना, केवल तभी, इसमें उचित होगा कानून द्वारा प्रदान किए गए दो वाक्यों में से छोटे को अधिरोपित करना। अन्य में शब्दों में, प्रमाण की प्रकृति का इससे कोई लेना-देना नहीं है सजा का चरित्र। प्रमाण की प्रकृति कर सकती है। केवल दोषसिद्धि के प्रश्न पर सहन करें-चाहे या नहीं आरोपी

दोषी साबित हो गया है। अगर अदालत आती है। यह निष्कर्ष कि अपराध को घर लाया गया है अभियुक्त और दोषसिद्धि इसके बाद आती है।

21. हाथ में मामले में, हम देखते हैं कि आरोपी एक हताश पिता है। मृतक कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। पिता अपनी बेटी को पूरे प्यार से पालता है और स्नेह। लेकिन एक सुबह वह उसे दूसरे व्यक्ति से शादी करने के लिए छोड़ देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हर बड़ी बेटी को शादी के बाद घर से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी, इसे कैसे कम किया जाता है या प्रदर्शन किया जाता है, यह एक कारक है, जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

22. इस मामले में मृतक और पीडब्लू 16 दोनों अपने स्कूल के दिनों से ही प्यार में थे। वह भाग जाती है और एक उप-पंजीयक के सामने शादी कर लेती है। वास्तव में, कोई भी पिता निश्चित रूप से ऐसी स्थिति और भावनाओं से निराश होगा और उथल-पुथल, जिससे वह गुजरता है, बोतलबंद हो जाता है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि घटना के दिन सभी भावनाएं भड़क गई हैं और उसने अपनी बेटी की हत्या करने का चरम कदम उठाया है। हमारा मानना है कि मामले अभियोजन पक्ष को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग । के तहत लाया जा सकता है।''

विवादित फैसले के निकाले गए हिस्से से, यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया है कि आईपीसी की धारा 300 में दिए गए पांच अपवादों में से किसी एक में मामले को कैसे शामिल किया जाएगा। जब तक मामला

निर्दिष्ट अपवादों में से किसी एक के अंतर्गत नहीं आता है, इसे आईपीसी की धारा 304 के पहले भाग या दूसरे भाग के तहत नहीं लाया जा सकता है (देखें हरेंद्र नाथ मंडल बनाम बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 435)। सबसे पहले अपवाद केवल तभी आकर्षित किया जाएगा जब यह अभिनिर्धारित करना संभव हो कि अभियुक्त गंभीर और अचानक उकसावे से आत्म-नियंत्रण की शक्ति से वंचित होने के बावजूद मृत्यु का कारण बना। अभिलेख पर स्थापित तथ्यों से, यह देखा जाता है कि अपीलकर्ता ने अपनी बेटी शिल्पा का गाँव की महिलाओं के सार्वजनिक शौचालय में पीछा किया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया। घातक चोटों के परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसलिए, पहले अपवाद का कोई उपयोग नहीं होगा। दूसरा अपवाद उन मामलों में आकर्षित किया जाएगा जहां अभियुक्त, निजी रक्षा के अधिकार का सद्भावना से प्रयोग करते हुए, कानून द्वारा उसे दी गई शक्ति से अधिक हो जाता है और चोट पहुँचाता है जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पीड़ित बिना पूर्व-चिंतन के और इस तरह के बचाव के उद्देश्य के लिए आवश्यक से अधिक नुकसान करने के किसी भी इरादे के बिना। यह अपवाद भी वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होगा। तीसरा अपवाद लोक सेवक के मामले में आकर्षित किया जाएगा या जनता की उन्नति के लिए कार्य करने वाले लोक सेवक की सहायता करने वाला व्यक्ति न्याय। यह अपवाद वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है। चौथा अपवाद तब आकर्षित होता है जब अपराध को पूर्व-चिंतन के बिना किया जाता है, अचानक झगड़े पर जुनून की गर्मी में अचानक लड़ाई में और अपराधी के अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना। यहाँ तक कि इस अपवाद का भी इस तथ्य स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वर्तमान मामला। पाँचवाँ अपवाद तब आकर्षित होता है जब वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु 18 वर्ष से अधिक आयु के होने के कारण हुई है, मृत्यु का शिकार होता है या अपनी सहमति से मृत्यु का जोखिम उठाता है। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी का बचाव, जैसा

कि आई.डी. 1 की धारा 313 के तहत उसके बयान से स्पष्ट होता है, पूरी तरह से इनकार करने और गलत तरीके से फंसाने का है।

29. यह देखने के लिए पर्याप्त है कि आईपीसी की धारा 300 में से कोई भी अपवाद वर्तमान मामले में आकर्षित नहीं है। यह अनिवार्य रूप से अनुसरण करेगा कि आरोपी (अपीलार्थी) ने अपनी बेटी शिल्पा की हत्या कर दी सजा की वृद्धि को निरपेक्ष बनाया जाता है-जिससे दोषी ठहराया जाता है। अपीलार्थी (अभियुक्त) आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

31. तदनुसार, अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है और सजा बढ़ाने के लिए कारण दिखाएँ नोटिस को पूर्ण बना दिया जाता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराना और आजीवन कारावास की सजा सुनाना।

कल्पना केः त्रिपाठी याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।